जनसत्ता

महंगाई की मार

अभी तक तो पेट्रोल और डीजल के दाम ही महंगाई बढ़ा रहे थे, लेकिन अब प्याज के दाम भी आमजन के आंसू निकाल रहे हैं। शायद ही कोई साल ऐसा गुजरता है जब दीपावली के महीने-डेढ़ पहले प्याज के दाम आसमान न छूने लगते हों। आमतौर पर पंद्रह से बीस रुपए किलो बिकने वाला प्याज अब अस्सी-नब्बे रुपए तक बिक रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में यही हालत है। यह चिंता और परेशानी की बात ज्यादा इसलिए है कि प्याज रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है, लेकिन सरकारें बेफिक्र हैं। लग रहा है उन्हें प्याज के दाम बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हालत यह है कि इस बार प्याज के दाम पिछले चार साल में सबसे ज्यादा चढ़े हैं। सरकारें जानती हैं कि हर साल सितंबर-अक्तूबर में प्याज के दाम बढ़ते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर कोई कदम नहीं उठाए गए। वरना आज लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, वे नहीं होते। राजधानी दिल्ली में वर्ष 2015 के बाद का यह पहला मौका है जब प्याज के दाम सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव (महाराष्ट्र) में भी प्याज साठ रुपए किलो बिक रहा है। नाशिक में यही भाव चल रहा है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि देश के दूसरे हिस्सों में क्या हाल होगा।

प्याज महंगा होने के पीछे सबके अपने-अपने तर्क हैं। कारोबारी कह रहे हैं कि देश में प्याज का स्टॉक काफी कम है, जिसके कारण मंडियों में आवक कम हो रही है। ऐसे में खपत के मुकाबले अगर मंडियों में आवक कम होगी तो दाम बढ़ने स्वाभाविक हैं। मंडियों में प्याज नहीं पहुंच पाने की वजह यह है कि दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर प्याज की फसल चौपट हो गई। नई फसल आने में अभी वक्त है। इससे भी संकट गहराया है। हालांकि यह चक्र हर साल का है। अक्तूबर-नवंबर में नई फसल आने से पहले प्याज का स्टॉक कम ही रहता है। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा फायदा जमाखोर उठाते हैं। सरकारें भी इस बात को अच्छी तरह समझती हैं, लेकिन जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि सरकारें प्याज का पर्याप्त भंडार होने का दावा करती रहती हैं, फिर भी बाजार में किल्लत बनी रहती है। सरकारी दुकानों और भंडारों से रियायती दामों पर प्याज बेचने की योजनाएं भी चलाई जाती हैं। पर यहां भी जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले पीछा नहीं छोड़ते और सस्ता प्याज लेकर महंगा बेचने का खेल करते रहते हैं।

बाजार में प्याज की किल्लत न हो और रियायती दाम पर लोगों को प्याज मिले, इसके लिए राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर प्रयास तो करती हैं, लेकिन प्याज गरीब की पहुंच से दूर ही है। भारत से कई देशों को प्याज का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। इसलिए पहला कदम यह उठाया गया है कि प्याज का निर्यात कम किया जाए और देश में पर्याप्त आपूर्ति बनाई रखी जाए। इस साल जून में भी जब प्याज के दाम में इजाफा हुआ था, तब सरकार ने निर्यात पर नियंत्रण के मकसद से प्याज निर्यात पर दी जाने वाली दस फीसद की सबसिडी वापस ले ली थी। निर्यात बढ़ने से प्याज का स्टाक कम हो जाता है और इसका असर घरेलू मांग पर पड़ता है। सवाल इस बात का है कि जब पता है कि एक खास मौसम में यह संकट होता है तो आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए क्यों नहीं पहले से तैयारी की जाती?

दोहरेपन की हद

हाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आतंकवाद को शह देने में अपने यहां की कुछ एजेंसियों की भूमिका को जिस तरह खुलेआम दुनिया के सामने स्वीकार किया था और उसे गलत बताया था, उससे यह उम्मीद बंधी थी कि अब वे अपने देश के लिए नए रास्ते की खोज कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह खामखयाली कुछ दिन भी बनी नहीं रह सकी। कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हाफिज सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया था और उसी वजह से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे थे। इसी से बने दबाव के बाद बीती जुलाई में पाकिस्तान सरकार ने भी हाफिज सईद को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और उसके सभी बैंक खातों पर पाबंदी लगा थी। लेकिन ऐसा कर-के तारीफ हासिल करने के अभी तीन महीने भी नहीं बीते हैं कि पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में यह गुहार लगाई कि हाफिज सईद का परिवार संकट से जूझ रहा है, इसके मद्देनजर उसे खर्चे के लिए बैंक खाते को दोबारा इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। अफसोस यह है कि सुरक्षा परिषद ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद फैलाने में हाफिज सईद की भूमिका जगजाहिर होने के बावजूद पाकिस्तान की यह मांग मंजूर कर ली।

हो सकता है कि पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार किए जाने का मुख्य कारण हाफिज सईद के परिवार की स्थिति और मानवाधिकारों से जुड़े तकाजे हों। लेकिन सवाल है कि अगर किसी को हाफिज सईद के परिवार की तकलीफों से सहानुभूति है तो अनिवार्य होने पर क्या वह उसके लिए अलग से मदद की व्यवस्था नहीं करा सकता था? जो व्यक्ति दुनिया भर में आतंक फैलाने का सूत्रधार हो और जिसे खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा हो, उसे बैंक खाते पैसे निकालने की इजाजत का औचित्य समझना मुश्किल है। महज करीब ढाई महीने पहले दुनिया के सामने हाफिज सईद को गिरफ्तार करके वाहवाही हासिल करने वाली पाकिस्तान सरकार के सामने आखिर वह कौनसी मजबूरी पैदा हो गई कि उसे उसी के लिए सुविधा की फरियाद करनी पड़ी? हाल में आतंकवाद के खिलाफ अपनी भूमिका को लेकर दुनिया को आश्वस्त करने के बाद पाकिस्तान सरकार के इस आधिकारिक रुख की आखिर क्या वजहें हो सकती हैं? गौरतलब है कि हाफिज सईद 2008 के मुंबई हमले का मुख्य आरोपी रहा है। 2006 में मुंबई में ट्रेन धमाकों और 2001 में संसद पर हमले में इसका हाथ माना जाता रहा है। करीब छह महीने पहले पाकिस्तान सरकार ने हाफिज के संगठनों जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत पर पाबंदी लगा दी थी।

दरअसल, ऐसा दोहरापन शायद पाकिस्तान के स्वभाव में घुल चुका है कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कुछ और कहता है और जब उस पर अमल का सवाल आता है तो अक्सर उसके उलट बर्ताव करता है। पिछले कुछ दिनों के दौरान कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान ने जिस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया है, वह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि भारत से संबंधों में सुधार की कोशिश करने के उसके दावे कितने खोखले हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि भारत को जिस पैमाने के आतंकवाद की समस्या से दो-चार होना पड़ा है, उसमें पाकिस्तान की भूमिका क्या रही है। इस तरह के तथ्य बार-बार सामने आते रहे हैं कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान स्थित ठिकानों से भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां संचालित करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को यह साफ करने की जरूरत है कि वह आतंकवादियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों से मदद की गुहार लगा कर आतंकवाद के खिलाफ किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है!

कल्पमेधा

न उधार दो, न उधार लो, क्योंकि उधार देने से अक्सर धन और मित्र, दोनों खो जाते हैं। उधार लेने से मितव्ययिता कुंठित हो जाती है।
- शेक्सपियर

हमले से उपजते संकट

विकेश कुमार बडोला

सउदी अरब के अरामको सहित अनेक तेल उत्खनन प्रतिष्ठानों की चार दशक पहले अमेरिकी सहयोग से जो प्रगति हुई और जिस आधार पर वैश्विक तेल व्यापार सबसे उन्नत हुआ, वह अमेरिका-सउदी अरब के लिए अति लाभकारी सिद्ध हुआ। रूस, चीन और ईरान को इससे बड़ा झटका लगा था। वैश्विक प्रतिबंधों के बाद भी ईरान का गुप्त परमाणु हथियार परीक्षण कार्यक्रम इसी घटना की प्रतिक्रिया है।

सउदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर ड्रोन हमलों ने वैश्विक बाजार में पेट्रो पदार्थों के मूल्यों में भारी वृद्धि कर दी है। इराक के बाद भारत दूसरा देश है, जो सउदी अरब से सबसे ज्यादा अपना अस्सी फीसद तेल आयात करता है। रूस और अमेरिका भी सउदी अरब के दो बड़े तेल ग्राहक हैं। ऐसे में महत्त्वपूर्ण देशों को तेल की आपूर्ति रुक जाने से वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता, अर्थव्यवस्था में मंदी और अनेक दूसरे दुष्प्रभाव पड़ने शुरू हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने सउदी अरब को भरोसा दिया है कि वह जल्द ही अरब से तेल की आपूर्ति के काम को सामान्य बनाने के लिए उसकी सहायता करेगा। सउदी अरब पर कच्चे, प्रसंस्करित और अन्य प्रकार के तेलों और पेट्रो उत्पादों पर निर्भर रहने वाले देशों के लिए अचानक यह एक प्रमुख चिंता बन चुकी है।

इस साल अप्रैल में अरामको ने दक्षिण कोरियाई तेल रिफाइनरी हुंडई ऑयल बैंक में तेरह फीसद की हिस्सेदारी अर्जित करने के लिए सवा अरब अमेरिकी डॉलर देकर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अरामको ने पालैंड की प्रमुख तेल रिफाइनरी पीकेएन ऑर्लेन के साथ उसे अरबी कच्चे तेल की आपूर्ति करने के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इतना ही नहीं, अरामको तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन के नए-नए कीर्तिमान स्थापित करती रही है। इसी क्रम में वह अब विश्व के सबसे प्रमुख तरलीकृत प्राकृतिक गैस उत्पाद बनाने की योजना भी बना रही है। अरामको एलएनजी बाजार में छा जाने का अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए क्षमतावान संयुक्त उद्यमों और साझीदारों की खोज में है। संभवतः यही कारण थे, जो अरब केंद्रित और ईरान-यमन-जॉर्डन आधारित तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादों के मध्य गलकाट प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के प्रमुख कारक रहे हैं।

तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सउदी अरब अरामको जैसे उत्कृष्ट तेल उत्खनन प्रतिष्ठान के नेतृत्व में तेल एवं प्राकृतिक गैस के कारोबार में एकाधिकार की स्थिति में आ चुका है। लेकिन ईरान में सरकार के समानांतर जो असंतुष्ट, विद्रोही और अराजक धनसंपन्न सत्ता-वर्ग पिछले पांच-छह दशकों में तैयार हुआ। वह ईरानी सरकार के गुप्त संरक्षण में ईरान के लिए चुनौती बने सउदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों को हानि पहुंचाने का जोखिम उठाने लगा है। इसका ताजा उदाहरण है अरामको पर हुआ ड्रोन हमला है। एक प्रकार से यह ईरान की सउदी अरब और अमेरिकी कारोबारी मित्रता से चिढ़-कुढ़ कर किया गया सामरिक प्रतिवाद है। इसे सउदी अरब और अमेरिका आसानी से भुला नहीं पाएंगे। हालांकि दोनों देशों का पहला दायित्व विश्व के देशों को सउदी अरब से होने वाली तेल की आपूर्ति को पूर्ववत स्थिति में लाना है, लेकिन ईरान और उसके सहयोगी इस्लामी देशों के संरक्षण में तेल प्रतिष्ठान पर ड्रोन से धावा करने वालों के प्रति अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। सउदी अरब भी यही चाहेगा कि उसके विरोध में मध्य-पूर्वी एशियाई देशों से उठने वाली विद्रोही लहर को येन-केन-प्रकारेण थाम लिया जाए।

अरामको जिसका आधिकारिक नाम साउबी अरबियन ऑयल कंपनी है और जो पहले (अरबियन-अमेरिकन ऑयल कंपनी) के रूप में नामांकित हो चुकी है, वह सउदी अरब की राष्ट्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस कंपनी है। यह देहरान, सउदी अरब में स्थित है। पिछले साल इसका कुल राजस्व 355.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था और कुल आय 111.1 अरब अमेरिकी डॉलर थी। कंपनी का सौ फीसद स्वामित्व सरकार के पास है। इसमें बासठ हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं। यह दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली तेल कंपनी है। अरामको विश्व के एकमात्र दीर्घ हाइड्रोकॉर्बन नेटवर्क का संचालन करती है। कंपनी सउदी अरब में सौ से ज्यादा तेल एवं गैस क्षेत्रों का प्रबंधन करती है, इनमें विश्व का सबसे बड़ा तटवर्ती तेल क्षेत्र घावर फील्ड और विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र सफानिया फील्ड भी शामिल है।

सउदी अरब के अरामको सहित अनेक तेल उत्खनन प्रतिष्ठानों की चार दशक पहले अमेरिकी सहयोग से जो प्रगति हुई और जिस आधार पर वैश्विक तेल व्यापार सबसे उन्नत हुआ, वह अमेरिका-सउदी अरब के लिए अति लाभकारी सिद्ध हुआ। रूस, चीन और ईरान को इससे बड़ा झटका लगा था। वैश्विक प्रतिबंधों के बाद भी ईरान का गुप्त परमाणु हथियार

परीक्षण कार्यक्रम इसी घटना की प्रतिक्रिया है। भले रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन अरामको तेल उत्खनन प्रतिष्ठान पर हुए ड्रोन हमले के लिए ईरान को निर्दोष बता रहे हैं और अमेरिकी विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो हमले का दोषारोपण ईरान पर किए जाने को अप्रामाणिक बता रहे हों, पर इस संदर्भ में भारत का आत्ममंथन यदि स्वतंत्र होगा तो उससे पूर्णतः यही सिद्ध होगा कि सउदी अरब द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में की गई प्रगति पर ईरान जैसे मुसलिम देशों की दृष्टि अनुकूल तो कम से कम नहीं ही है।

सउदी अरब और ईरान मूलतः मुसलिम देश होकर भी शिया और सुन्नी में विभाजित हैं। इसी आधार पर उनके सामाजिक और व्यापारिक मतभेद पनपते रहे हैं। रूस, ईरान के पक्ष में इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसकी सामरिक और वैज्ञानिक प्रगति के उत्पाद खरीदने के लिए ईरान और उसके पिछलग्गू मुसलिम देश भी बड़े ग्राहक हैं। फिर रूस मध्य-पूर्वी मुसलिम देशों के बल पर अपनी वैश्विक कूटनीति का प्रसार करने का परंपरागत अवसर भी नहीं चूकना चाहता। यह भी हो सकता है कि विश्व के विकसित देशों के गुटतंत्र में उपेक्षित छूट जाने के अपमान का बदला रूस ने ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन की उन नीतियों का समर्थन करके किया है जो उसके संज्ञान में उसके मित्र राष्ट्र भारत सहित कई दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के लिए आत्मघाती हैं। उसे चूंकि विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जैसे-तैसे अपनी पहचान बनाए रखनी है, इसलिए अब अरामको पर हमले के संदर्भ में ईरान की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अथवा चाही-अनचाही हर प्रकार की भूमिका पर वह परदा डालना चाहता है।

ईरान के समर्थन में खड़े यमन के हूती विद्रोही अरब केंद्रित मुसलिमों से शिया-सुन्नी आधार पर धार्मिक मतभेद रखते आए हैं। सउदी अरब की उन्नति उनकी दृष्टि में हमेशा खटकती रही है। वे अरब को सदैव कोई न कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं। पिछले महीने ही ओमान की खाड़ी में तेल के दो टैंकरों को विस्फोट कर उड़ाया गया था। जांच और प्रमाण के बाद यही सिद्ध हुआ कि ईरान के गुप्त संकेत पर यमन के हूती विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों ने विस्फोट किया। हालांकि अपने आरक्यू-4 ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन की सहायता से अमेरिका ने विस्फोट के बाद घटनास्थल की सघन जांच करनी चाही, परंतु ईरान ने अमेरिकी ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए थे। तब से ईरान और अमेरिका के बीच कटुता पहले से ज्यादा बढ़ गई है।

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगा हुआ है। अमेरिकी आदेश के अनुसार वह भारत सहित कई देशों को अपने तेल की आपूर्ति नहीं कर सकता। इससे उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है। परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका, ईरान से पहले ही खफा है। किसी तरह ट्रंप ईरान से परमाणु संधि पर बात करने को राजी हुए थे, परंतु अरामको पर दो दिन पहले हुए ड्रोन हमले अब संधि पर चर्चा का दरवाजा बंद कर चुके हैं। हमले के बाद अरामको से तेल आपूर्ति ठप हो चुकी है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसका दुष्प्रभाव भारत पर भी अवश्य पड़ेगा। ईरान से पहले ही तेल की आपूर्ति बंद है। ऐसे में अरामको संयंत्र पर हमला नई वैश्विक ऊर्जा समस्या उत्पन्न कर चुका है।

पर्यावरण के हक में

राकेश सोहम्

दुनिया मेरे आगे

एक साहित्यिक विमर्श के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि सड़क के किनारे पन्नी खाती गाय को देख कर ख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने उसे अपने व्यंग्य में उकेरा है। वह स्थिति आज भी उतनी ही गंभीर बनी हुई है। पन्नियां घटी नहीं, बल्कि बढ़ती ही गईं और आए दिन शहरों में न जाने कितनी ही गायें पन्नियों को खाकर बीमार होती हैं या फिर मर जाती है। आज इसके खिलाफ की जाने वाली तमाम बातों के बावजूद हालत में कितना बदलाव आया है। मेरे दिवंगत पिता पशु चिकित्सक थे। मुझे याद है कि उन्होंने कितनी ही गायों का ऑपरेशन करके पेट से पन्नियों का ढेर निकाले जाने की चर्चा की थी। आश्चर्य है कि गाय को लेकर आम लोग कई बार हमलावर होने की हद तक संवेदनशील होते हैं, लेकिन पन्नी खाकर उनके मरने को लेकर उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। अधिकतर लोग बाजार से खरीदारी करने के बाद सामान के लिए पन्नियों का ही उपयोग करते हैं। हर रोज शाम को हाथ हिलाते हुए बिचरने जाते हैं और लौटते वक्त दोनों हाथों की पांचों अंगुलियों में सब्जियों से भरी पन्नियों की थैलियां घर लाते हैं।

हमारी परंपरा में चीजों के बारंबार उपयोग में विश्वास है। अक्सर 'यूज एंड थ्रो' यानी 'इस्तेमाल करो और फेंक दो' वाली चीजों का भी हम बार-बार उपयोग करने से नहीं चूकते हैं। प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और डिब्बे अधिकतर घरों में बार-बार धोकर उपयोग में लाए जाते हैं। देश में पॉलिथीन की थैलियों का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ी-सी सुविधा के चलते लोग कपड़े से बने थैलों की अपेक्षा पॉलिथीन की थैलियों को ज्यादा उपयोगी समझ रहे हैं और धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे विश्व में प्रति मिनट कितना प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह तकनीकी जानकारी भी देना उचित नहीं लगता कि कितने माइक्रोन की पॉलिथीन का उपयोग करना चाहिए। दरअसल, उपयोगकर्ता चाहे कितना ही पढ़ा-लिखा क्यों न हो, इतनी निपुणता नहीं रखता कि वह नियत माइक्रोन की पॉलिथीन की बनी थैलियों को चुनाव कर सके। इसलिए प्लास्टिक को पूरी तरह 'न' कहा जाए, इस बात पर जोर दिया जाना ज्यादा जरूरी है। अब इसके व्यापक नुकसानों और पर्यावरण पर घातक असर को देखते हुए राजनीतिकों की ओर से भी इस पर पाबंदी की बातें की जाने लगी हैं, लेकिन सच यह है कि पर्यावरणविद लंबे समय से इस बारे में देश और समाज को चेतावनी देते रहे हैं। अगर वक्त रहते देश के राजनीतिक वर्ग और समाज ने इसके प्रति कोई ठोस संकल्प नहीं लिया, तो आने वाले वक्त में इसका भयावह खमियाजा उठाना पड़ सकता है।

कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि कचरे के ढेर से अपनी भूख मिटाती गायें अचानक बीमार पड़ गईं। खाना-पीना बंद कर दिया था, उनके पेट बुरी तरह फूल गए थे और फिर कई गायों की तड़प-तड़प कर मौत हो गई थी। गायों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उनकी आहार नलिका पॉलिथीन की थैलियों से बुरी तरह अवरुद्ध हो गई थी। ऑपरेशन से जो थैलियों का कचरा आंत से निकाला गया, उनमें से अधिकतर थैलियों में घरों से फेंका गया अतिरिक्त खाना अब भी सुरक्षित था। ऐसा केवल इसलिए हुआ कि लोग घर लाई गई पॉलिथीन की थैलियों को फेंकने के पहले उनमें घर की अतिरिक्त खाद्य सामग्री, फलों या सब्जियों के छिलके आदि को भर कर रख देते हैं। फिर इसको पोटलीनुमा बना कर फेंक देते हैं। कचरे के ढेर से अपनी भूख मिटाते जानवर इन पोटलियों को साबुत निकल जाते हैं।

भारत तीज-त्योहार और उत्सवों का देश है। जगह-जगह मंदिर निर्मित किए गए हैं। इनमें पूजन प्रसाद का वितरण प्लास्टिक की थैलियों, कटोरिया और ग्लासों में किया जाता है। भक्त और दर्शनार्थी इस प्रसाद को श्रद्धापूर्वक ले तो लेते हैं, लेकिन प्रसाद को खाने के बाद लापरवाही से सड़क पर फेंक देते हैं। इनमें बचा हुआ प्रसाद जानवरों को आकर्षित करता है और वे उसे निगल लेते हैं। कमोबेश सभी पर्यटन स्थलों की स्थिति भी ठीक नहीं है। मैं पांच साल मुंबई में पदस्थ था। एक सपना लेकर गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया से खूबसूरत नीले समुद्र को निहारूंगा। लेकिन वहां की हालत देख कर सारे सपने टूट गए। मुंबई के अधिकतर समुद्र तट पानी की खाली प्लास्टिक के बोतलों से अटे पड़े थे। ज्यादातर पर्यटक लापरवाही से खाली बोतलें समुद्र में उछाल देते हैं।

मुझे किसी फिल्म का एक वीभत्स दृश्य याद आता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सिर पर पॉलिथीन की थैली इस तरह पहना देता है कि उसकी सांस अवरुद्ध हो जाती है। उखड़ती सांसों के साथ फूलती-पिचकती पॉलिथीन देख कर जी दहल जाता है। तो क्या हम मनुष्यों का जीवन भी इसी तरह प्लास्टिक की पन्नियों के अंधाधुंध प्रयोग से अवरुद्ध हो जाएगा? क्या अब चेतने का समय नहीं आ गया है?

नई पीढ़ी का दम

आज पूरी दुनिया में ग्रेटा थनबर्ग की चर्चा है, जिसने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में वैश्विक नेताओं पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से निपटने में नाकाम रहने और अपनी पीढ़ी से विश्वाघात करने का आरोप लगाया। थनबर्ग ने जोर देकर कहा कि जब विश्व गंभीर पर्यावरण संकट से गुजर रहा है और दुनिया के नेता पैसे के बारे में और आर्थिक विकास की काल्पनिक कथाओं के बारे में बात कर रहे हैं। उसने वैश्विक नेताओं से पूछा- ऐसा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इस सवाल पर सभी निरुत्तर थे। इस सोलह वर्षीय लड़की का गुस्सा इसलिए भी फूटा क्योंकि ट्रंप ने जलवायु सम्मेलन के बजाय एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की प्राथमिकता दी थी। यह वाकई प्रतिरोध का विषय है। भारत में भी युवा मन और युवा शक्ति चाहे तो देश की बिगड़ी हुई तस्वीर-तकदीर बदल सकती है, उसे संवार सकती है, लेकिन ऐसा कम हो रहा है। शायद इसलिए भारत बीते सत्तर बरसों से विकासशील है। आज का युवा देश की आवाज है, लेकिन बेरोजगारी के कारण राजनीतिक पार्टियां अपने निजी फायदे लिए उन्हें गुमराह कर रही हैं। सच्चे राजनीतिक लोगों की जगह सत्ता और धनलोलुप लोगो ने ले ली है। नौजवानों को चाहिए कि वह अपनी सोच को नई दिशा दें। हर नई शुरुआत का आगाज नए खून से ही होता है। हम केवल इसलिए पिछड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जोश का सकारात्मक उपयोग नहीं किया है। निराश, हताश, असमंजस में खड़ा युवा कैसे विकास पथ पर बढ़े, देश को बढ़ाए, हमें इस पर गहराई से मंथन करना होगा।

● *संतोष कुमार, बेगूसराय*

गलत फैसला

ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कलई खुल गई है। अब वे न घर के रहे, न घाट के। अपनी राष्ट्रवादी राजनीति से उन्होंने महारानी एलिजाबेथ को भी कलंकित कर दिया है। एक अनपढ़ बच्चा भी यही कहेगा कि पांच हफ्तों के लिए संसद को स्थगित कराना, ब्रेग्जिट के मुद्दे पर मुश्किल बहसों से खुद को बचाना ही था। अब प्रश्न उठता है कि क्या ब्रिटेन इस समय संवैधानिक संकट में फंस गया है? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां लिखित संविधान ही नहीं है। इसलिए वह प्रधानमंत्री के गैरकानूनी कदम का दर्द झेल रहा है। जिन बावन फीसद अंग्रेजों ने ब्रेग्जिट की रायशुमारी में यूरोपियन यूनियन से अलग होने की हामी भरी थी, उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। अब तीन रास्ते दिख रहे हैं। यूरोपियन संघ से और मोहलत मांग कर फिर से रायशुमारी कराई जाए या देश को मध्यावधि चुनाव में धकेला जाए।

● *भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत*

बदहाल बैंक

पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के कामकाज पर पाबंदी लगा दी गई है। ग्राहकों का पैसा बैंक में फंस गया है। अभी कोई भी ग्राहक छह महीने में सिर्फ दस हजार रुपए ही निकाल पाएगा। यह वाकई गंभी संकट की स्थिति है। इस घटना ने लोगों को एक बार फिर से नोटबंदी के दिनों की याद दिला दी। घोटाले में फंसे पीएमसी बैंक की घटना हमारे बैंकिंग तंत्र की कलई खोलती है। लोगों के पैसे पर ताला लगा कर रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाया है उससे तो लोगों का बैंकों पर से विश्वास उठ गया है। अब लोग बैंकों में अपने पैसे रखने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस श्रेणी में सरकारी, अर्धसरकारी सभी बैंक निशाने पर हैं। ऐसे फैसले भी देश की अर्थव्यवस्था व्यवस्था को मंदी की ओर ले धकेलने वाले साबित हुए हैं। जनता भले ही कुछ न कह रही हो, मगर वह अपने आप को ठगा महसूस कर रही है।

● *मोहम्मद आसिफ, जामिया नगर दिल्ली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बेलगाम मंच

सोशल मीडिया का दुरुपयोग आज गंभीर संकट बन गया है। इस समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर लगाम कसने की जरूरत बताई है। शीर्ष अदालत ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल दिशानिर्देश तैयार करे। अदालत ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर संदेश सामग्री उपलब्ध करवाने वाले का पता लगाना एक गंभीर मुद्दा है। आजकल शहरों, प्रदेशों और देश में अफवाहें और झूठी खबरें फैलाने में सोशल मीडिया का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इस माध्यम से लोगों को निजी रूप से हानि भी पहुंचाई जा रही है। किसी को गाली दे देना धमकी देना या अभद्र शब्द का प्रयोग करना आम बात हो गई है। भीड़ हिंसा के मामले भी सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बढ़े हैं। समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने का काम किया जा रहा है। फेक न्यूज भी इसी के जरिए फैलाई जाती है। अगर वाकई में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाया गया तो देश में हिंसक घटनाएं तेजी से बढ़ने लगेंगी।

● *राजू, गोरखपुर*

संकट का तापमान

न्यूयार्क में जलवायु संकट पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन से पहले वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले पांच साल अब तक के इतिहास में दर्ज सबसे गर्म साल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी बढ़ोतरी होने से समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है। डब्ल्यूएमओ ने आगाह किया है कि कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए तत्काल प्रयास किए जाने की जरूरत है। संस्था की रिपोर्ट में बढ़ती गर्मी के प्रभावों और कारणों पर हाल के वर्षों में नवीनतम जानकारियों का एक संकलन पेश किया गया है। मानवजनित कारणों से भी धरती का तापमान बढ़ रहा है जिससे गर्मी, लू और जंगलों में आग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन पर अब भी ध्यान नहीं देंगे और पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं करते तो यह भविष्य के लिए और भी खतरनाक होगा। धरती का तापमान औद्योगिक क्रांति के वक्त के स्तर से दो डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़े, इसके लिए प्रयासों में तीन गुना तेजी लाने की आवश्यकता है।

● *निवेदिता मलिक, मोदीनगर*